

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
लोक सभा
06.08.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2876 का उत्तर
तमिलनाडु में एक स्टेशन एक उत्पाद

2876. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश भर में राज्यवार विशेषकर तमिलनाडु में एक स्टेशन एक उत्पाद (ओएसओपी) पहल के अंतर्गत शामिल किए गए रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है;
- (ख) तमिलनाडु में रेलवे स्टेशनों पर ओएसओपी योजना के अंतर्गत पहचाने गए और प्रचारित किए गए स्थानीय उत्पादों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) ओएसओपी पहल में उक्त राज्य के स्थानीय कारीगरों, लघु उद्योगों और स्वयं-सहायता समूहों को शामिल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;
- (घ) तमिलनाडु में रेलवे स्टेशनों पर ओएसओपी इकाइयों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता और अवसंरचनात्मक सुविधाएँ क्या हैं; और
- (ङ) उक्त राज्य में ओएसओपी उत्पादों के प्रचार के संबंध में किए गए प्रभाव मूल्यांकन/प्राप्त प्रतिक्रिया क्या है और इस योजना का और विस्तार करने की क्या योजना है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य के 166 स्टेशनों सहित भारतीय रेल में 1,984 स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद (ओएसओपी) योजना संचालित की जा रही है।

रेल मंत्रालय द्वारा 'एक स्टेशन एक उत्पाद' (ओएसओपी) योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य भारत सरकार के 'वोकल फॉर लोकल' दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, स्वदेशी उत्पादों के

लिए बाजार उपलब्ध कराना और रेल यात्रियों को भारत की समृद्ध विरासत का अनुभव कराना और स्थानीय कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों, जनजातियों आदि द्वारा बनाए गए स्थानीय/स्वदेशी उत्पादों को खरीदने के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उस क्षेत्र में स्वदेशी रूप से निर्मित/उगाए गए प्रसंस्कृत, अर्ध प्रसंस्कृत और अन्य खाद्य उत्पादों को भी खरीदने का अवसर प्रदान करना है।

इस योजना के अंतर्गत, भारतीय रेल स्वदेशी/स्थानीय उत्पादों के प्रदर्शन, बिक्री और उन्हें उच्च दृश्यता प्रदान करने के लिए विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किए गए विक्रय केंद्र प्रदान करता है। समाज के सबसे निचले तबके/हाशिए पर और कमज़ोर वर्गों, स्वयं सहायता समूहों आदि को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए कोई वित्तीय पात्रता नहीं है। इस योजना के उद्देश्यों को पूरा करने वाले सभी आवेदकों को आबंटन किया जाता है। इस योजना में भाग लेने के लिए नाममात्र पंजीकरण शुल्क है। साथ ही, 15 दिनों की अवधि के लिए 20 यूनिट बिजली निःशुल्क प्रदान की जाती है।

तमिलनाडु में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्तशिल्प और कलाकृतियां, वस्त्र और हथकरघा, पारंपरिक परिधान और स्थानीय कृषि उत्पाद कोटियों को प्रसारित एवं बेचा जाना शामिल है।

योजना के शुभारंभ (25.03.2022) से लेकर 30.06.2025 तक, तमिलनाडु में इस योजना के तहत कुल ₹22.08 करोड़ की बिक्री हुई है। भारतीय रेल विभिन्न स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य स्थानीय उत्पादकों को इस योजना में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया और स्टेशन सूचना पट्टों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है।
